Panchayati Raj Institutions (PRIs)

पंचायती राज संस्थाएँ

Panchayati Raj Institutions (PRIs)

- Panchayati Raj Institutions (PRIs) refer to the system of ‘Rural Local Self-Governance’ in India i.e. a system of governance of Rural Areas through the representatives elected by the people./ पंचायती राज संस्थान (PRI) भारत में 'ग्रामीण स्थानीय स्वशासन' की प्रणाली को कहते हैं, यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का शासन करने की प्रणाली।

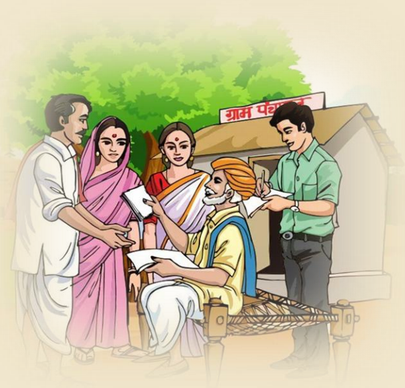

- They have been established in all States as the third tier of government, aiming to build democracy at the grassroots level./ इन्हें सभी राज्यों में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना है।

- It was constitutionalised through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992./ इसे 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

Evolution of Panchayati Raj / पंचायती राज का विकास

Balwant Rai Mehta Committee / बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- The first such committee was the Balwantrai Mehta Committee, appointed by the Government of India in 1957./ पहली ऐसी समिति बलवंतराय मेहता समिति थी, जिसे भारत सरकार ने 1957 में नियुक्त किया था।
- To examine the working of the Community Development Programme (1952) and the National Extension Service (1953)./ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम (1952) और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस (1953) के कामकाज की जांच करना।
- Establishment of a three –tier panchayati raj system – gram panchayat at the village level, panchayat samiti at the block level and zila parishad at the district level./ तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना - गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
- These tiers should be organically linked through a device of indirect elections./ ये स्तर अप्रत्यक्ष चुनावों के ज़रिए आपस में जुड़े होने चाहिए।
- The village panchayat should be constituted with direct elections/ ग्राम पंचायत का गठन सीधे चुनावों से होना चाहिए।

Evolution of Panchayati Raj / पंचायती राज का विकास

- Panchayat Samiti and Zilla Parishad: constituted with indirectly elected/ पंचायत समिति और जिला परिषद: अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों से गठित।
- Chairman of the Zilla Parishad: District collector/ जिला परिषद का अध्यक्ष: जिला कलेक्टर
- Based on the recommendations of the Balwantrai Mehta Committee, most of the states in India established PRIs by the mid-1960s./ बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत के ज़्यादातर राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक PRIs की स्थापना की।
- Rajasthan was the first state in India to establish PRIs in the year 1959./ राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने 1959 में PRIs की स्थापना की।
- Andhra Pradesh was the second state in India to establish PRIs in the same year 1959/ आंध्र प्रदेश उसी साल 1959 में PRIs स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य था।

Ashok Mehta committee (1977)

- In December 1977, the Janata Government appointed a committee on Panchayati Raj institutions under the chairmanship of Ashok Mehta./ दिसंबर 1977 में, जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की।
- It submitted its report in August 1978 and made 132 recommendations./ इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 132 सिफारिशें कीं।
- Three-tier system of Panchayati raj should be replaced by the two-tier system – zilla parishad and mandal panchayat (consisting of a group of villages with a total population of 15,000 to 20,000)/ पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली को दो-स्तरीय प्रणाली - जिला परिषद और मंडल पंचायत (15,000 से 20,000 की कुल आबादी वाले गांवों के समूह से मिलकर) से बदल दिया जाना चाहिए।
- District as first point for decentralisation under popular supervision below the state level./ राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए जिले को पहला बिंदु बनाया जाए।

Ashok Mehta committee (1977)

- Official participation of political parties at all levels of panchayat elections./ पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी।
- Compulsory powers of taxation to PRIs to mobilise own financial resources./ अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए PRIs को अनिवार्य कराधान शक्तियां दी जाएं।
- Regular social audit by a district level agency and by a committee of legislators to ascertain spending mandate./ खर्च के जनादेश का पता लगाने के लिए जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की एक समिति द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट।
- Elections should be held within six months from the date of supersession, if any/ यदि कोई हो, तो पद से हटाने की तारीख से छह महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए।
- Minister for Panchayati raj in the state council of ministers./ राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री।
- Reservation of Seats for SCs and STs on the basis of their population./ उनकी आबादी के आधार पर SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण।
- Constitutional recognition should be accorded to the PRIs, which will ensure sanctity and stature and an assurance of continuous functioning./ PRI को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, जिससे पवित्रता और कद सुनिश्चित होगा और लगातार काम करने का आश्वासन मिलेगा।

G. V. K. Rao committee (1985)

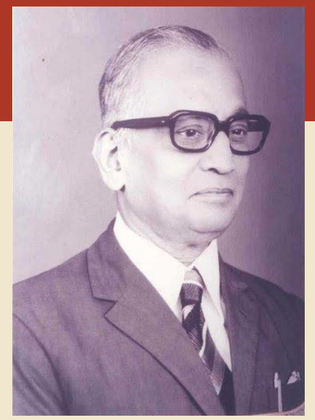

- Committee to review the existing “Administrative Arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes”./ मौजूदा “ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था” की समीक्षा करने वाली समिति।
- Zilla Parishad (District level body) should be of pivotal importance in the scheme of democratic decentralisation./ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना में जिला परिषद (जिला स्तर का निकाय) का मुख्य महत्व होना चाहिए।
- A post of District Development Commissioner should be created. He should act as the chief executive officer of the Zilla Parishad and should be in charge of all the development departments at the district level./ जिला विकास आयुक्त का एक पद बनाया जाना चाहिए। वह जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और जिला स्तर पर सभी विकास विभागों का प्रभारी होगा।
- Regular elections to the Panchayati Raj institutions/ पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव

L M Singhvi Committee (1986)

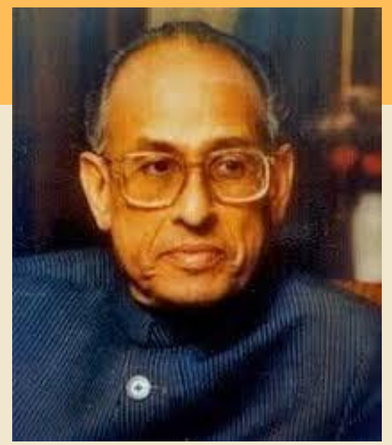

- In 1986, Rajiv Gandhi Government appointed a committee to prepare a concept paper on ‘Revitalisation of Panchayati Raj Institutions for democracy and development’ under the chairmanship of L.M Singhvi./ 1986 में, राजीव गांधी सरकार ने एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को फिर से मज़बूत बनाने' पर एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की।

Recommedations/ सिफारिशें :

- The panchayati Raj institutions should be constitutionally recognized , protected and preserved./ पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।
- Nyaya Panchayat should be established for a cluster of villages./ गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए।
- The village panchayats should have more financial resources./ ग्राम पंचायतों के पास ज़्यादा वित्तीय संसाधन होने चाहिए।
- Judicial tribunals should be established in each state to adjudicate controversies about election to the Panchayati Raj institutions, their dissolution and other matters related to their functioning./ पंचायती राज संस्थानों के चुनाव, उनके भंग होने और उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामलों पर विवादों का निपटारा करने के लिए हर राज्य में न्यायिक ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने चाहिए।

Thungon Committee (1988)

- In 1988, a sub-committee of the consultative Committee of Parliament was constituted under the chairmanship of P.K. Thungon. / 1988 में, संसद की सलाहकार समिति की एक सब-कमेटी पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी।

Recommendations/ सिफारिशें:

- To examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning./ ज़िला प्लानिंग के मकसद से ज़िले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना।
- Constitutional recognition to Panchayati Raj bodies./ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना।
- Three-tier system of PRIs with panchayats at the village, block and district levels./ गांव, ब्लॉक और ज़िला लेवल पर पंचायतों के साथ PRIs की तीन-स्तरीय प्रणाली।
- Zilla Parishad should act as the pivot of planning and development agency in the district./ ज़िला परिषद को ज़िले में प्लानिंग और विकास एजेंसी के मुख्य केंद्र के रूप में काम करना चाहिए।

Thungon Committee (1988)

- Fixed tenure of five years to PRIs./ पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच साल तय किया गया है।
- The maximum period of super session of a body should be six months./ किसी संस्था को सुपरसीड करने की अधिकतम अवधि छह महीने होनी चाहिए।
- A detailed enumerations of subjects for Panchayati Raj should be prepared and incorporated in the Constitution./ पंचायती राज के लिए विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।
- Reservation of seats in all the three-tiers – SC, ST, Women./ तीनों स्तरों पर सीटों का आरक्षण – SC, ST, महिलाएँ।
- State finance commission should be set-up in each state./ हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
- Chief executive officer of the Zilla Parishad- district collector./ जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिला कलेक्टर।

Gadgil committee (1988)

- The Committee on Policy and Programmes./ पॉलिसी और प्रोग्राम पर कमेटी।
- Constitutional status should be bestowed on the Panchayati Raj institutions./ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
- Three-tier system of Panchayati Raj with panchayats at the village, block and district levels./ गांव, ब्लॉक और जिला लेवल पर पंचायतों के साथ पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली।
- Fixed five years term of Panchayati Raj institutions./ पंचायती राज संस्थाओं का निश्चित पांच साल का कार्यकाल।
- Direct elections for members of the Panchayats at all the three levels./ तीनों लेवल पर पंचायतों के सदस्यों के लिए सीधे चुनाव।
- Reservation for SCs, STs and women proportionate with their population./ SC, ST और महिलाओं के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण।
- Establishment of a State Finance Commission for the allocation of finances to the Panchayats./ पंचायतों को फाइनेंस के बंटवारे के लिए एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना।
- Establishment of a State Election Commission for the conduction of elections to the panchayats./ पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।

73rd constitutional Amendment Act of 1992

- New part IX to the constitution, eleventh schedule consisting 29 functional items of the panchayats./ संविधान में नया भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं।
- Part IX: Article 243 To Article 243 O./ भाग IX: अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 O तक।
- Democratic shape to Article 40 (DPSP): “state to organise the village panchayats and provide them powers and authority so they can function as self-government.”/ अनुच्छेद 40 (DPSP) को लोकतांत्रिक रूप देना: “राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करना होगा और उन्हें शक्तियां और अधिकार देने होंगे ताकि वे स्वशासन के रूप में कार्य कर सकें।”
- The act has two parts: compulsory and voluntary./ इस अधिनियम के दो भाग हैं: अनिवार्य और स्वैच्छिक।
- Compulsory Provisions: must be added to state laws, which includes the creation of the new Panchayati Raj systems./ अनिवार्य प्रावधान: इन्हें राज्य कानूनों में जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें नई पंचायती राज प्रणालियों का निर्माण शामिल है।
- Voluntary Provisions: on the other hand, are at the discretion of the state government./ स्वैच्छिक प्रावधान: दूसरी ओर, राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर हैं।

Features of the 73rd Constitutional Amendment Act in Panchayati Raj

Gram Sabha 243A: Village assembly consisting of all the registered voters within the area of the panchayat.
पंचायत क्षेत्र के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स से मिलकर बनी गांव की सभा।

Three-tier System: At village, intermediate and district level. States with a population less than 20 lakhs may not constitute the intermediate level.
गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वे मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं कर सकते हैं।

Election of members and chairperson (243K): The members to all the levels of the Panchayati Raj are elected directly and chairperson to the intermediate and the district level is elected indirectly from the elected members and at the village level the Chairperson is elected as determined by the state government.
सदस्यों और चेयरपर्सन का चुनाव (243K): पंचायती राज के सभी लेवल के सदस्य सीधे चुने जाते हैं और इंटरमीडिएट और जिला लेवल पर चेयरपर्सन चुने हुए सदस्यों में से इनडायरेक्टली चुने जाते हैं और गांव लेवल पर चेयरपर्सन का चुनाव राज्य सरकार द्वारा तय तरीके से होता है।

Reservation of seats (Article 243 D)

- The act provides for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in every panchayat in proportion of their population./ यह एक्ट हर पंचायत में उनकी आबादी के अनुपात में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटों के रिज़र्वेशन का प्रावधान करता है।
- The act provides for the reservation of not less than one-third of the total number of seats for women (including the number of seats reserved for women belonging the SCs and STs)./ यह एक्ट महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटें रिज़र्व करने का प्रावधान करता है (इसमें SC और ST से संबंधित महिलाओं के लिए रिज़र्व सीटों की संख्या भी शामिल है)।
- The act also authorizes the legislature of a state to make any provisions for reservation of seats in any panchayat or offices of chairperson in the Panchayat. यह एक्ट किसी राज्य के विधानमंडल को किसी भी पंचायत में या पंचायत में चेयरपर्सन के पदों पर सीटों के रिज़र्वेशन के लिए कोई भी प्रावधान करने का अधिकार भी देता है।

Duration of Panchayats (Article 243 E)

- The act Provides for a five year term of office to the Panchayat at every level from the date of its first meeting./ यह एक्ट हर लेवल पर पंचायत को उसकी पहली मीटिंग की तारीख से पांच साल का कार्यकाल देता है।
- However it can be dissolved before the completion of its term./ लेकिन इसे इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है।

Disqualifications (243 F)

- A person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of panchayat if he is so disqualified/ कोई भी व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए अयोग्य माना जाएगा यदि वह
- Under any law for the time being in force for the purpose of elections to the legislature of the state concerned./ संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के उद्देश्य से इस समय लागू किसी भी कानून के तहत अयोग्य है।
- Under any law made by the state legislature./ राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत।
- 21 years to be the minimum age for contesting elections to panchayats./ पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

- **State Election Commission for Each State:** The state legislature may make provision with respect to all matters relating to elections to the panchayats. SEC conducts elections for Panchayats and Municipalities./ राज्य विधानमंडल पंचायतों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। SEC पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव करवाता है।

- **Powers and Functions 243 G:** The state legislature may endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government./ राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
  - ✓ The preparation of plans for economic development and social justice./ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी।
  - ✓ The implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them, including those in relation to the 29 matters listed in the Eleventh Schedule./ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, जो उन्हें सौंपे जा सकते हैं, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं।

Finances 243 H

- The state legislature may,/ राज्य विधानमंडल,
- Authorise a panchayat to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees./ किसी पंचायत को टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस लगाने, इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने का अधिकार दे सकता है।
- Assign to a panchayat taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government/ राज्य सरकार द्वारा लगाए और इकट्ठा किए गए टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस किसी पंचायत को सौंप सकता है।
- Provide for making grants-in-aid to the panchayats from the consolidated fund of the state./ राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से पंचायतों को ग्रांट-इन-एड देने का प्रावधान कर सकता है।
- Provide for the constitution of funds for crediting all money of the panchayats./ पंचायतों के सभी पैसे जमा करने के लिए फंड बनाने का प्रावधान कर सकता है।

Finance Commission 243 I

- Governor of a state shall, after every five years, constitute a finance commission to review the financial position of the panchayats and make recommendations thereof. / राज्य का गवर्नर हर पांच साल बाद पंचायतों की फाइनेंशियल स्थिति का रिव्यू करने और उस पर सुझाव देने के लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाएगा।

Audit of Accounts 243 J

- State legislature may make provisions for the maintenance and audit of panchayat accounts./ राज्य विधानमंडल पंचायत खातों के रखरखाव और ऑडिट के लिए प्रावधान बना सकता है।

Application to Union Territories 243 L

- The president may direct the provisions of the act to be applied on any union territory subject to exceptions and modifications he specifies./ राष्ट्रपति इस एक्ट के प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें वे कुछ छूट और बदलाव बता सकते हैं।
- Exempted States and Areas: The act does not apply to the states of Nagaland, Meghalaya and Mizoram and certain other areas. These areas include-The scheduled areas and the tribal areas in the states/ छूट वाले राज्य और क्षेत्र: यह एक्ट नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं- राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र
- The hill area of Manipur for which a district council exists and/ मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद है और
- Darjeeling district of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists/ पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है

Bar to interference by courts 243 O

- It further lays down that no election to any panchayat is to be questioned except by an election petition presented to such authority and in such manner as provided by the state legislature.

- इसमें आगे यह भी कहा गया है कि किसी भी पंचायत के चुनाव पर तब तक सवाल नहीं उठाया जा सकता, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा बताए गए तरीके से और उसी अथॉरिटी के सामने इलेक्शन पिटीशन पेश न की जाए।

PESA Act of 1996

The PESA act, 1996 stands for the Panchayat Extension to the Scheduled Areas.
It was enacted by the Government of India to extend the provisions of part IX of the Constitution to the scheduled areas mentioned under 244 (1).

Objectives :

- to empower Gram Sabhas in the scheduled areas.
- Safeguard and preserve the traditions, customs and cultural identity of tribal people.
- Manage community resources.
- Ensure local self genvernance that respects tribal ways of life.

States covered/ कवर किए गए राज्य

- **PESA applies to 10 states having fifth scheduled areas:**

पेसा 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों पर लागू होता है:

- ✓ Andhra Pradesh
- ✓ Chhattisgarh
- ✓ Gujarat
- ✓ Himachal Pradesh
- ✓ Jharkhand
- ✓ Madhya Pradesh
- ✓ Maharashtra
- ✓ Odisha
- ✓ Rajasthan
- ✓ Telangana

Important Article related to Panchayats

Article No.	Subject – Matter (विषय – वस्तु)
Article 243	• Definitions / परिभाषाएँ
Article 243A	• Gram Sabha / ग्राम सभा
Article 243B	• Constitution of Panchayats / पंचायतों का गठन
Article 243C	• Composition of Panchayats / पंचायतों की संरचना
Article 243D	• Reservation of seats / सीटों का आरक्षण
Article 243E	• Duration of Panchayats / पंचायतों की अवधि
Article 243F	• Disqualifications for membership / सदस्यता के लिए अयोग्यता
Article 243G	• Powers, authority and responsibilities of Panchayats / पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व
Article 243H	• Powers to impose taxes by, and funds of the Panchayats / पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनके कोष
Article 243I	• Constitution of Finance Commission to review financial position / वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन

Important Article related to Panchayats

Article No.	Subject – Matter (विषय – वस्तु)
Article 243J	• Audit of accounts of Panchayats / पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण
Article 243K	• Elections to the Panchayats / पंचायतों के चुनाव
Article 243L	• Application to Union Territories / संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना
Article 243M	• Part not to apply to certain areas / कुछ क्षेत्रों पर यह भाग लागू नहीं होगा
Article 243N	• Continuance of existing laws and panchayats / विद्यमान कानूनों और पंचायतों की निरंतरता
Article 243O	• Bar to interference by courts in electoral matters / चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक

Question : 1

Which part of the constitution deals with the Panchayats?

संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है?

(a) Part X / भाग X

(b) Part IX / भाग IX

(c) Part VII / भाग VII

(d) Part IV / भाग IV

(SSC CGL 23/09/2024)

Question : 2

Which of the following states is not of those states that have no Panchayati Raj Institutions?

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से नहीं है जहाँ पंचायती राज संस्थाएँ नहीं हैं?

(SSC CGL 25/09/2024)

(a) Punjab / पंजाब

(b) Gujarat / गुजरात

(c) Nagaland / नागालैंड

(d) Assam / असम

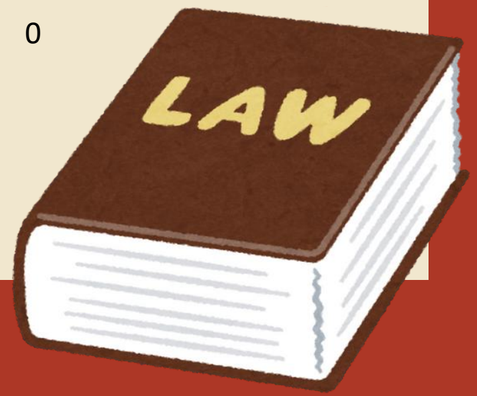

Question : 3

The election to constitute a Panchayat should be completed before the expiration of a period of ___ from the date of its dissolution.

पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तिथि से ___ की अवधि समाप्त होने से पहले पूरे कर लिए जाने चाहिए।

(a) Eight months / आठ महीने

(b) One year / एक वर्ष

(c) Six months / छह महीने

(d) Two months / दो महीने

(SSC CHSL 14/10/2020)

Question : 4

Article 243K of the constitution deals with which of the following?

संविधान का अनुच्छेद 243K निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) Duration of the Panchayat / पंचायत की अवधि

(b) Grounds of disqualification from membership of Panchayat / पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता के आधार

(c) Reservation of seats in Panchayat / पंचायत में सीटों का आरक्षण

(d) Election to the Panchayat / पंचायत के चुनाव

(SSC CHSL 20/03/2023)

Question : 5

A Panchayat continue for ___ from the date appointed for its first meeting.

पंचायत अपनी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से ___ तक कार्य करती है।

(a) 14 years

(b) 11 years

(c) 5 years

(d) 9 years

(SSC MTS 18/10/2021)

Question : 6

The elections to the Panchayati Raj Institutions are conducted by the ___

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ___ द्वारा कराए जाते हैं।

(a) Central Election Commission / केंद्रीय चुनाव आयोग

(b) State Government / राज्य सरकार

(c) State Election Commission / राज्य चुनाव आयोग

(d) Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग

(SSC CGL 2020)

Question : 7

When was the third tier added to Indian Federal System?

भारतीय संघीय व्यवस्था में तीसरा स्तर कब जोड़ा गया था?

(a) 1990

(b) 1991

(c) 1992

(d) 1993

(UPPCS 2020)

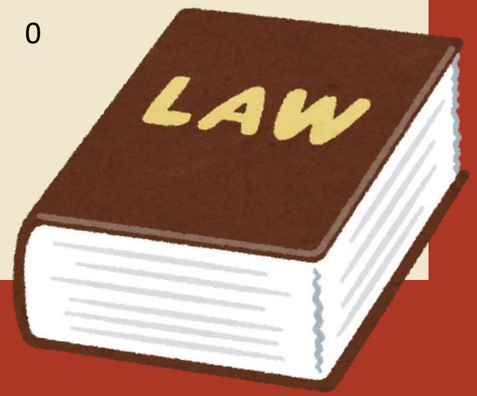

Question : 8

Which Article gives the list of 29 functions to be performed by the Panchayati Raj Institutions?

कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची प्रदान करता है?

(a) Article 243(H)

(b) Article 243(E)

(c) Article 243(F)

(d) Article 243(G)

(BPSC PRE 2020)

Question : 9

Which of the following is not a part of the Eleventh Schedule of the constitution?

निम्नलिखित में से कौन संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची का भाग नहीं है?

(a) Libraries / पुस्तकालय

(b) Fuel and fodder / ईंधन और चारा

(c) Rural sports / ग्रामीण खेल

(d) Technical training / तकनीकी प्रशिक्षण

(BPSC PRE 2022)

Question : 10

The reservation of seats for women in Panchayats has been provided by an amendment to constitution of India. That amendment is __

पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भारतीय संविधान में एक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। वह संशोधन है __

(a) 70th amendment of 1992 / 1992 का 70वां संशोधन

(b) 73rd amendment of 1992 / 1992 का 73वां संशोधन

(c) 74th amendment of 1992 / 1992 का 74वां संशोधन

(d) 77th amendment of 1994 / 1994 का 77वां संशोधन

(RAS PRE)

ANSWER KEY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B	C	C	D	C	C	D	D	C	B